the earliest. In conclusion, let me say that even with all your might... ...*(Interruptions)*...

श्री सामिक भट्टाचार्य : सर, ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. ...(*Interruptions*)...

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) सर, ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Nothing is going on record. Please sit down. Yes, hon. Leader of the Opposition.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: उपसभापति महोदय, हम इस सदन में सभी मैम्बर्स का आदर करते हैं और आप हमें बार-बार यह कहते हैं कि सभी लोग रूल्स के मुताबिक बात करें, अपनी बात रखें। यदि कोई एक मैम्बर कुछ बात कहता है, तो उसको interrupt करना - एक बार नहीं, बल्कि बार-बार करते हैं, हर वक्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उधर से उठता है, अपनी बात रखता है, तो एक माननीय सदस्य हर वक्त वहाँ से उठकर हाउस को हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। आप उन्हें expel कीजिए। ...(**व्यवधान**)... You expel him. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय एलओपी का सुझाव अच्छा है और सभी सदस्य, सभी पक्ष के लोग इसका पालन करें। ...(**व्यवधान**)...आप सही कह रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...आप बैठ जाइए। Shri Naresh Bansal; demand for 'Green Bonus' and special package for the State of Uttarakhand. सभी माननीय सदस्य इसका पालन करें, एक-दूसरे के बारे में टोका-टाकी न करें। ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record.

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Samirul Islam: Ms. Sushmita Dev, (West Bengal), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Ms. Dola Sen (West Bengal), Dr. Sarfraz Ahmad (Jharkhand), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Ramji (Uttar Pradesh) Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal) and Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana).

Now, Shri Naresh Bansal.

Demand for 'Green Bonus' and special package for the State of Uttarakhand

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड) : उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं उत्तराखंड से आता हूं, जो कि एक हिमालयी राज्य है। उत्तराखंड आदरणीय अटल जी ने दिया था और माननीय नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा उसे सँवारने का काम निरंतर जारी है। मोदी जी के कार्यकाल में हर क्षेत्र में, चाहे वह कृषि हो, बागवानी हो, शिक्षा हो, मेडिकल हो, चारधाम पुनर्निर्माण हो, ऑल वैदर रोड, एयर कनेक्टिवटी रोड हो, रेल कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में पूरे सहयोग के साथ बहुत-सी योजनाओं का लाभ उत्तराखंडवासियों को मिल रहा है।

महोदय, उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थिति देश के बाकी राज्यों के अलग है। यहाँ, जहाँ एक ओर प्राकृतिक सौंदर्य एवं संपदा की बहुतायत है व पर्यावरण स्वच्छ है, वहीं दूसरी तरफ एक विषम समस्या भी है। हिमालयी राज्यों के सतत विकास के लिए एक स्वतंत्र नीति बनाने की मांग एक लंबे समय से चल रही है, क्योंकि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियाँ देश के अन्य हिस्सों से अलग हैं।

महोदय, विषम भौगोलिक हालत की वजह से यहाँ पर विकास कार्य काफी प्रभावित होता है और योजनाओं के पूरा होने में समय लगता है। कई परियोजनाएं लंबे समय से इसी कारण से लटकी पड़ी हैं। महोदय, जो कार्य मैदानी राज्यों में सहजता से हो जाता है, वह काम पर्वतीय राज्यों में श्रम व आर्थिक लिहाज से काफी मुश्किल हो जाता है। पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक और सामाजिक संरचना के अनुसार विकास की पृथक्क नीति बनानी अति आवश्यक है। उत्तराखंड इस मुद्दे को शुरू से ही उठाता रहा है।

महोदय, उत्तराखंड राज्य की सामान्य आबादी 1.20 करोड़ है, लेकिन यदि पर्यटन, विभिन्न धार्मिक यात्राओं, पर्वों एवं त्योहारों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को जोड़ा जाए, तो यह 8 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। राज्य की इतनी बड़ी आबादी के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है।

महोदय, दूसरी ओर, उत्तराखंड पिछले एक दशक से ज्यादा समय से देश के लिए दे रहा अपनी पर्यावरणीय सेवाओं के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज व ग्रीन बोनस की मांग करता रहा है। उत्तराखंड का वनाच्छादित क्षेत्र, ग्लेशियर, सदानीरा नदियाँ उत्तराखंड से ज्यादा लाभ देश के अन्य भागों को देती हैं। वैश्विक पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ता है। एक आकलन के अनुसार उत्तराखंड हर वर्ष अपनी जैव विविधता के ज़रिये देश को 95 हज़ार, 112 करोड़ रुपये की सेवाएं देता है। जहाँ उत्तराखंड के पास इतनी प्राकृतिक संपदा है, वहीं विकास की राह में वह पिछड़ रहा है, अत: इसकी भरपाई ग्रीन बोनस से ही बनती है।

महोदय, उत्तराखंड का विशेष पैकेज, जो अटल जी ने दिया था, वह तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। अगर यह प्रोत्साहन मिले तो उत्तराखंड में तेजी से औद्योगिकीकरण हो सकता है। महोदय, उत्तर-पूर्वी राज्यों की तरह ही...(**समय की घंटी**)...

उपसभापतिः धन्यवाद श्री नरेश बंसल जी। The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Naresh Bansal: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Mayankbhai Jaydevbhai Nayak (Gujarat), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Dr. Kalpana Saina (Uttrakhand), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh),

Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Rajasthan), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Dorjee Tshering Lepcha (Sikkim), Dr. Sangeeta Balwant (Uttar Pradesh) and Shrimati Sadhna Singh (Uttar Pradesh).

Shri Beedha Masthan Rao Yadav; regarding supply of SPF P. monodon brood stock to the registered Shrimp hatcheries.

Supply of SPF P. monodon brood stock to the registered Shrimp hatcheries

SHRI BEEDHA MASTHAN RAO YADAV (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for giving me the opportunity. This is regarding supply of monodon brood stock to our Indian aqua farmers. Government of India through Coastal Aquaculture Authority of India approved the supply of brood stock of monodon by the following two empanelled suppliers vide dated 17.02. 2020. And, the second one is M/s Aquaculture De La Mahajamba, Madagascar. This empanelment is for continued supply of SPF brood-stock of Monodon to demanding Indian shrimp hatcheries and, in turn, they will produce seed and supply to the Indian aqua farmers. In view of the demand of Monodon post-larvae i.e., seed by our shrimp farmers, hatchery operators approached these SPF brood-stock suppliers for their specific quotation and terms and conditions for supply of SPF brood-stock. But, there has been no response from the concerned suppliers. They were empanelled by the Ministry after their Expression of Interest and personal presentation as indicated in the order.

Both these firms are supplying brood-stock to only one hatchery under each of them which, essentially, leads to monopoly in sale of post-larvae. It means, instead of 50 paisa per PPL, these monopoly companies are supplying at Rs. 1.50 to aqua farmers in India which we believe that the concerned authority or the Ministry will never permit.

Sir, monopoly is being established by the firm which was permitted by the Government of India for establishment of Brood-stock Multiplication Centre of SPF Monodon by procuring parent post-larvae from the empanelled overseas SPF producer. That is the reason why they prevent direct supply of SPF brood-stock by the overseas SPF producer empanelled by the Government to Indian hatcheries. Since there is no response for our supply request to both empanelled overseas firms, we would request your kindself to do the needful, so that they will confirm supply of SPF brood-stock to all the Indian registered hatcheries. An early action in this regard will help shrimp production levels in the country.